

गरवी गुजरात

PRGI No. UPHIN/25/A1697

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM LUCKNOW, AHMEDABAD, SURAT

वर्ष : 02
अंक : 194
दि. 15.11.2026, रविवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा
LUACKNOW EDITION

'भारतीय क्रिकेट के लिए शानदार दिन', अंडर-19 टीम की जीत पर ढट मोदी समेत कई नेताओं ने दी शुभकामनाएं

अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में जीत के बाद भारतीय टीम को देशभर से बधाइयां मिल रही हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, समेत कई नेताओं ने युवा खिलाड़ियों की तारीफ की. ढट मोदी ने कहा कि टीम की सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी.

(जीएनएस)।

नई दिल्ली, पाकिस्तान के खिलाफ अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में भारतीय टीम ने ऐसी जीत दर्ज की, जिसने पूरे देश को जश्न मनाने का मौका दे दिया. आखिरी गेंद तक चले रोमांचक मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को एक विकेट से हरा दिया. इस शानदार जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के कई बड़े नेताओं ने भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी. पीएम मोदी ने युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर गर्व जताया. उन्होंने कहा कि टीम की सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर भारतीय टीम को बधाई दी. उन्होंने लिखा कि भारतीय क्रिकेट के लिए शानदार दिन. हमारे युवा क्रिकेटरों के आज के बेहतरीन प्रदर्शन और पुरुष अंडर-19 एशिया कप 2026 जीतने पर मुझे बहुत गर्व है. उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी. पीएम मोदी ने टीम को आगे के सफर के लिए शुभकामनाएं भी दीं.

अमित शाह बोले- रोमांचक जीत, खिलाड़ियों ने दिखाया दम

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी भारतीय टीम की जीत को शानदार बताया. उन्होंने लिखा कि यह एक रोमांचक जीत है. अमित शाह ने टीम को बधाई देते हुए कहा कि खिलाड़ियों ने अपने जज्बे, दृढ़ संकल्प और खेल भावना से देश का मान बढ़ाया है. उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देश की क्रिकेट प्रतिभा की शानदार मिसाल बताया. शाह ने कहा कि टीम का यह प्रदर्शन कई नए खिलाड़ियों को क्रिकेट की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा.

योगी आदित्यनाथ ने कहा- मैदान में फिर गूंजा भारत का विजयघोष

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी भारतीय टीम को बधाई दी. उन्होंने पर लिखा कि खेल के मैदान में फिर गूंजा भारत का विजयघोष. योगी ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर चैंपियन बनी भारतीय टीम के हर खिलाड़ी का अभिनंदन किया. उन्होंने देशवासियों को भी इस जीत की बधाई दी.

धामी और सम्राट चौधरी ने भी की खिलाड़ियों की तारीफ

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने



शानदार खेल कौशल, कड़ी मेहनत और टीम भावना के दम पर यह जीत हासिल की है. उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि से देश का मान बढ़ा है. बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी टीम को बधाई दी. उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ियों ने अपने जज्बे, प्रतिभा और शानदार खेल से हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है.

रेखा गुप्ता बोलीं- भारत के खिलाड़ियों ने दबाव में दिखाया दम

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इस मुकाबले को शानदार बताया. उन्होंने लिखा, "क्या मैच था, क्या शानदार अंत था." रेखा गुप्ता ने कहा कि पाकिस्तान के सामने 338 रन का लक्ष्य था और फाइनल का दबाव भी काफी ज्यादा था. पाकिस्तान के पास रन थे, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों के पास दबाव झेलने का हौसला था. उन्होंने आखिरी गेंद तक चले मुकाबले में खिताब जीतने पर अंडर-19 टीम को बधाई दी.

आखिरी गेंद पर चौका लगाकर भारत ने जीता खिताब

भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा. पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 337 रन बनाए थे. इसके जवाब में भारतीय टीम को 338 रन का लक्ष्य मिला. भारत की पारी के दौरान लगातार विकेट गिरते रहे और मुकाबला आखिरी ओवर तक पहुंच गया. टीम को आखिरी गेंद पर जीत के लिए तीन रन चाहिए थे. ऐसे में मोहित उलवा ने चौका लगाकर भारत को जीत दिला दी. भारत ने एक विकेट से मुकाबला जीतकर अंडर-19 एशिया कप 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया.

कर्नाटकः पीएम मोदी के काफिले में शामिल हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी, मैसूर में ही फंसा रहा विमान

(जीएनएस)।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्नाटक यात्रा के दौरान उनके काफिले में शामिल वायु सेना के एक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण शुक्रवार को उसे ललित महल के पास जयाचमराजा वाडियार हेलीपैड पर ही रोकना पड़ा।

जानकारी के अनुसार, प्रधानमंत्री के काफिले के लिए वायु सेना के तीन हेलीकॉप्टर मैसूर पहुंचे थे। जब प्रधानमंत्री मोदी अपना निर्धारित कार्यक्रम पूरा कर वहां से रवाना होने वाले थे, ठीक उसी वक्त एक हेलीकॉप्टर में तकनीकी दिक्कत आ गई।



समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इस खराबी के बाद प्रधानमंत्री और उनके काफिले के अन्य सदस्य बाकी बचे दो सुरक्षित हेलीकॉप्टरों के जरिए अपनी आगे की यात्रा के लिए रवाना हो गए, जबकि तकनीकी खराबी वाला हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर ही खड़ा रहा।

इस बीच, स्थानीय पुलिस ने हेलीपैड के आसपास के इलाके की घेराबंदी कर दी है और खराब हुए हेलीकॉप्टर की सुरक्षा के लिए वहां सुरक्षा बढ़ा दी है। सुरक्षा इंतजामों के तहत मैसूर नगर निगम के कर्मचारियों को भी मौके पर तैनात किया गया है।

हालांकि, हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी की असल वजह क्या थी और यह दोबारा उड़ान भरने के लिए कब तक तैयार होगा, इस पर अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

पीएम मोदी कई कार्यक्रमों में हुए शामिल

इस घटना से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने प्रशांति कुटीरम स्थित स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह में शिरकत की। इसके अलावा उन्होंने बेंगलुरु में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया और तवारेकेरे से क्क्ट बैंगलोर स्टेशन तक मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर उसमें सफर भी किया।

कर्नाटक के अपने सभी कार्यक्रम संपन्न करने के बाद पीएम मोदी गुजरात पहुंचे, जहां उन्होंने बनासकांठा जिले के प्रसिद्ध अंबाजी मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना की।

महादेव ऑनलाइन सट्टा मामला : सीबीआई की 33 ठिकानों पर छापेमारी

नई दिल्ली, महादेव ऑनलाइन बुक सट्टा ऐप मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शिकंजा कसते हुए देश के 6 राज्यों में 33 ठिकानों पर छापेमारी की है। जांच एजेंसी ने यह कार्रवाई ऐप के पैनल ऑपरेटरों के ठिकानों पर की। छापेमारी के दौरान कई डिजिटल डिवाइस, मोबाइल फोन और अहम दस्तावेज जब्त किए गए हैं। सीबीआई के मुताबिक, इस कार्रवाई में सौरभ चंद्राकर से पूछताछ के दौरान सामने आई जानकारियों की अहम भूमिका रही है। ष्टक्कड्ड ने महादेव ऑनलाइन बुक के अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क के खिलाफ पिछले कुछ दिनों में व्यापक तलाशी अभियान चलाया। जांच एजेंसी की टीमें अमृतसर, दिल्ली, नागौर, धौलपुर, भोपाल, रायपुर, दुर्ग, इंदौर, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, मुंबई और नागपुर समेत कई शहरों में पहुंचीं।

आईएमडी ने 20 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान जताया, दिल्ली में हल्की धूप और मध्यम कोहरा रहने के आसार

(जीएनएस)।

नई दिल्ली, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने देश के कई हिस्सों में बारिश, आंधी-तूफान और तेज हवाओं का पूवार्नुमान जताया है। आने वाले दिनों में अलग-अलग क्षेत्रों में मौसम की स्थिति अलग-अलग रहने की संभावना है। मौसम विभाग के ताजा पूवार्नुमान के अनुसार, शनिवार को उत्तर प्रदेश और बिहार सहित लगभग 20 राज्यों में मौसम खराब रहने की संभावना है। कुछ इलाकों में 75 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। मौसम विभाग ने दक्षिण भारत और उत्तर-पश्चिम भारत के पहाड़ी इलाकों में आंधी-तूफान और बिजली गिरने की भी चेतावनी दी है। बारिश और तेज हवाओं के कारण 10 से ज्यादा राज्यों में तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है।



इसके अलावा, तीन राज्यों में बर्फबारी होने की संभावना है, जबकि पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में ओले गिर सकते हैं। आईएमडी ने लोगों को सतर्क रहने और स्थानीय मौसम संबंधी सलाह का पालन करने की सलाह दी है।

वहीं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार को धुंध भरी धूप और हल्का कोहरा रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में भारी बारिश की उम्मीद नहीं है, लेकिन धुंध और वायु प्रदूषण का उच्च स्तर विजिबिलिटी (दृश्यता) और बाहरी गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है।

धुंध और धुएं के बावजूद, नई दिल्ली में दिन के समय मौसम अपेक्षाकृत गर्म रह सकता है। अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है, जबकि सुबह और शाम के समय मौसम थोड़ा ठंडा रहेगा।

गुरु गोबिंद सिंह सामाजिक भेद मिटाने के लिए आजीवन प्रतिबद्ध रहे : अमित शाह

(जीएनएस)।

नई दिल्ली, गुरु गोबिंद सिंह के ज्योति ज्योत दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नमन किया। उन्होंने कहा कि गुरु साहिब सामाजिक भेद मिटाने के लिए आजीवन प्रतिबद्ध रहे। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अधर्म और अन्याय के विरुद्ध शौर्य व पराक्रम के प्रतीक, सरबंसदानी गुरु गोबिंद सिंह के ज्योति ज्योत दिवस पर कोटि-कोटि नमन। सामाजिक भेद मिटाने के लिए आजीवन कटिबद्ध रहे गुरु साहिब ने खालसा पंथ की स्थापना कर सिख धर्म को सेवा के साथ-साथ रक्षा का सशक्त स्तंभ बनाया। पिता, माता और चारों पुत्रों का बलिदान देकर भी स्वधर्म और स्वसंस्कृति के पथ से न डिगकर उन्होंने त्याग और समर्पण का जो कीर्तिमान रचा, वह अद्वितीय है। मानवता की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले दशम गुरु का जीवन अनंतकाल तक हर पीढ़ी का मार्गदर्शन करता रहेगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि धर्म, साहस, त्याग और अदम्य शौर्य के अमर प्रतीक, सिख पंथ के दसवें गुरु एवं खालसा पंथ के संस्थापक, दशमेश पिता गुरु गोबिन्द सिंह महाराज के ज्योति-ज्योत दिवस पर उनके पावन चरणों में कोटिशः नमन। गुरु गोबिन्द सिंह का सम्पूर्ण जीवन सत्य, न्याय और धर्म की रक्षा के लिए किए गए अद्वितीय संघर्ष, असीम त्याग और सर्वोच्च बलिदान की प्रेरणादायी मिसाल है। उन्होंने अपने साहस, तप और आध्यात्मिक तेज से मानवता को अन्याय के विरुद्ध निर्भीक होकर खड़े होने तथा राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए सर्वस्व समर्पित करने का मार्ग दिखाया। उनका अमर जीवन और महान विचार युगों-युगों तक मानवता को साहस, सेवा और धर्मनिष्ठा की प्रेरणा देते रहेंगे।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिखा कि महान धर्म-योद्धा, सिखों के दसवें गुरु, खालसा पंथ के संस्थापक, गुरु गोबिंद सिंह महाराज के पावन ज्योति ज्योत दिवस पर उनके चरणों में कोटि-कोटि नमन करता हूं। धर्म की रक्षा और मानवता के कल्याण के लिए समर्पित उनका पराक्रमी जीवन हम सभी को सर्वदा सत्य, सेवा और त्याग के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करता रहेगा। उनके पवित्र विचार सर्वदा मानवता के शुभत्व व मंगल का पथ प्रशस्त करते रहेंगे।



लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लिखा कि खालसा पंथ के संस्थापक एवं सिखों के दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह के ज्योति जोत दिवस पर उन्हें कोटिशः नमन। उनका संपूर्ण जीवन धर्म, सत्य, न्याय और मानवीय गरिमा की रक्षा के लिए किए गए अद्वितीय संघर्ष का अनुपम उदाहरण है। उन्होंने अपने विचारों, आध्यात्मिक चेतना और अदम्य साहस से समाज को अन्याय के विरुद्ध निर्भीक होकर खड़े होने की प्रेरणा दी। त्याग, तपस्या, वीरता और मानवता के प्रति समर्पण से ओतप्रोत उनका जीवन भारतीय आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक परंपरा की अमूल्य धरोहर है।

उनके आदर्श हमें सदैव धर्मनिष्ठा, परोपकार और कर्तव्यपालन के मार्ग पर अग्रसर होने की प्रेरणा देते रहेंगे।

शी और पुतिन से परमाणु हथियारों में कटौती पर बात करना चाहते हैं ट्रंप

वाशिंगटन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले हफ्ते प्रस्तावित एशिया यात्रा के दौरान चीनी और रूसी समकक्षों के साथ परमाणु हथियारों में कटौती पर चर्चा करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि, अमेरिकी अधिकारियों को इस त्रिपक्षीय बैठक से किसी समझौते के निकलने की उम्मीद नहीं है। व्हाइट हाउस की सहायक प्रेस सचिव ओलिविया वेल्स ने फिलीपींस और चीन की प्रस्तावित यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि चीन की यात्रा के समापन पर यह बैठक होगी। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि इस बातचीत का मकसद तुरंत कोई समझौता करना नहीं है, बल्कि यह परमाणु हथियारों के जखीरे को कम करने की दिशा में एक शुरूआती चर्चा है।

नाम न छापने की शर्त पर अधिकारी ने कहा, हमें किसी तरह के समझौते की उम्मीद नहीं है।



अधिकारी के अनुसार, ट्रंप की योजना चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक में ईरान के मुद्दे पर चर्चा करने की है, लेकिन यूक्रेन के इस एजेंडे में शामिल होने की संभावना नहीं है। यूक्रेन को लेकर रूस के साथ बातचीत अलग से चल रही है।

अधिकारी ने आगे बताया कि ट्रंप और पुतिन के बीच कोई द्विपक्षीय बैठक तय नहीं है, हालांकि वे अन्य कार्यक्रमों में एक साथ मौजूद रहेंगे।

परमाणु हथियारों पर यह चर्चा ट्रंप के उस दौरे का हिस्सा है, जिसमें क्षेत्रीय कूटनीति के साथ-साथ मौजूदा व्यापार समझौतों को लागू करने के प्रयास भी शामिल हैं। वेल्स ने बताया कि ट्रंप सोमवार सुबह वाशिंगटन से रवाना होंगे और स्थानीय समयानुसार मंगलवार शाम मनीला पहुंचेंगे।

फिलीपींस में, उनके क्वाड नेताओं से मिलने, थाईलैंड के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने और यूएस-आसियान विशेष शिखर सम्मेलन में भाग लेने का कार्यक्रम है। बुधवार के लिए एक राजकीय स्वागत समारोह, फिलीपींस के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक और एक भोज (बैंक्वेट) की योजना है।

इसके बाद ट्रम्प एपेक नेताओं के रात्रिभोज के लिए शेन्जेन जाएंगे। वेल्स ने बताया कि गुरुवार को एपेक नेताओं के साथ बैठकें होंगी, और शी जिनपिंग के साथ एक द्विपक्षीय बैठक तथा वर्किंग लंच का कार्यक्रम तय है।

एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि व्यापार के मोर्चे पर, चीन के साथ चर्चा का मुख्य जोर नए टैरिफ समझौते की घोषणा करने के बजाय मौजूदा समझौतों को लागू करने पर होगा।

यूएसः एयरलाइन संकट थमा नहीं, शनिवार की 2,000 से अधिक उड़ानें रद्द

(जीएनएस)।

वाशिंगटन, अमेरिका में शुक्रवार को घंटों तक चले देशव्यापी फ्लाइट ग्राउंड स्टॉप के बाद हवाई यातायात अभी भी सामान्य नहीं हो पाया है और इसमें समय लग सकता है। शनिवार को भी 2,000 से अधिक उड़ानें रद्द की गई हैं, जबकि सैकड़ों अन्य उड़ानों में देरी हो सकती है। एयरलाइंस रद्द और प्रभावित उड़ानों का बैकलॉग खत्म करने के साथ विमानों और क्रू की उपलब्धता सुनिश्चित करने में जुटी हैं। फ्लाइट डेटा ट्रैकर फ्लाइटअवेयर के अनुसार, शनिवार को अमेरिका के भीतर, वहां से बाहर जाने वाली और अमेरिका पहुंचने वाली 2,000 से अधिक उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। वहीं 300 से अधिक उड़ानों में देरी का अनुमान है। इससे पहले शुक्रवार को अमेरिका में 7,700 से अधिक उड़ानें रद्द हुईं और 8,000 से ज्यादा उड़ानों में देरी दर्ज की गई। शुक्रवार को एयर ट्रैफिक कंट्रोल केंद्रों में संचार संबंधी समस्याओं के कारण फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) ने देशभर में उड़ानों पर रोक लगा दी थी।



शुक्रवार शाम कुछ विमानों ने दोबारा उड़ान भरनी शुरू की। प्रमुख एयरलाइंस ने भी परिचालन बहाल करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। हालांकि, यात्रियों को सप्ताहांत तक उड़ानों में व्यवधान बने रहने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। एयरलाइंस के सामने रद्द उड़ानों के कारण विभिन्न हवाई अड्डों पर फंसे विमानों और उनके चालक दल को दोबारा व्यवस्थित करने की चुनौती है।

इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के हवाई यातायात ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए कांग्रेस से जल्द कानून पारित करने की अपील की है।

सीएनएन ने एक सूत्र के हवाले से बताया, ट्रंप ने शुक्रवार रात रिपब्लिकन सीनेटर एरिक श्मिट से फोन पर बातचीत के दौरान एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, एयरपोर्ट टावर, टर्मिनल और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए जल्द विधायी कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया।

सीनेटर श्मिट ने सितंबर में मॉडर्न स्काइज एक्ट पेश किया था। इस विधेयक के तहत अमेरिका के विमानन बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए अतिरिक्त 30 अरब डॉलर की संघीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। श्मिट चाहते हैं कि इस राशि को बजट सुलह प्रक्रिया में शामिल किया जाए, ताकि इसे जल्द मंजूरी मिल सके।

सूत्र के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन ने शुक्रवार सुबह देशव्यापी उड़ान रोक लगाए जाने से कुछ घंटे पहले ही कांग्रेस को पत्र भेजकर विमानन क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के लिए 30 अरब डॉलर की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था।



सम्पादकीय

भारत के मामले में यूएस का दखल

अनावश्यक शरारत अमेरिका के एक सरकारी आयोग ने दिल्ली दंगों के आरोपी शरजील इमाम को धार्मिक स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाने के कारण हिरासत में रखा गया व्यक्ति बताने पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दो टूक कहा कि अमेरिकी आयोग को भारत के नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर फैसला सुनाने का कोई अधिकार नहीं है।

दरअसल अमेरिकी आयोग ने जो भी फैसला शरजील के मामले में सुनाया है, वह अत्यंत आपत्तिजनक है क्योंकि वह अमेरिकी आयोग संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई इकाई नहीं है। यदि वह यूएनओ ही हो तो भी वह किसी संप्रभुता संपन्न राष्ट्र के नागरिक के मामले में किसी तरह के हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार रखता ही नहीं। भारत में नागरिकों को मिले मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए अदालतें मौजूद हैं। साथ ही अदालतें भारत के नागरिकों के खिलाफ आरोपों की जांच भी करती हैं।

वास्तविकता तो यह है कि अमेरिकी संस्थाएं दुनिया के हर मामले में अपना क्षेत्राकार सुरक्षित मानती है। भारत की कोई लुंजपुंज लोकतंत्र नहीं है। यहां लोकतांत्रिक संस्थाएं तो इतनी चुस्त दुरुस्त हैं कि एक थाना क्षेत्र की घटना पर दूसरे थाना क्षेत्र द्वारा जांच नहीं की जा सकती। शरजील अमेरिकी नागरिक नहीं है जिसके बारे में उनके आरोप में अपना विचार व्यक्त करने के नाम पर बकवास की है। अमेरिका की इन्हीं हरकतों से दुनिया का हर देश उससे परेशान है। यह सही है कि मानवाधिकार के मामले में दूसरे देश टिप्पणी कर देते हैं, फिर भी नहीं करना उचित नहीं है।

किन्तु किसी देश का सरकारी निकाय या आयोग जब अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करता है तो जानबूझकर शरारत करता है। रही बात अमेरिकी आयोग की तो इसने पक्षपातपूर्ण, अधूरी जानकारी के आधार पर और पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर यह फैसला सुनाया है।

बहरहाल अमेरिकी आयोग के शरजील इमाम संबंधी फैसले की कोई अहमियत नहीं है किन्तु यदि चिढ़ाने के लिए ही सही इस तरह की हरकत हुई है तो भारत को अमेरिका से साफ तौर पर कह देना चाहिए कि वह हमारे देश के नागरिकों की चिंता छोड़े अपने देश में मानवाधिकार, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और शिक्षा में व्याप्त भयंकर अपराधों पर ध्यान दे। भारत में सक्षम न्याय पालिका है जो सभी नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए केन्द्र व राज्य सरकारों और स्थानीय प्रशासन को चेतावनी देता रहता है। शरजील का मामला इतना गंभीर है कि उसे जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक तैयार नहीं है। सवाल उठता है कि जिस आरोपी पर भारत की सुप्रीम कोर्ट को दया नहीं आई उसको लेकर अमेरिकी आयोग इतना द्रवित क्यों हो रहा है? जवाब बिल्कुल स्पष्ट है कि इस तरह की बकवास अमेरिका में गुटबाज वकील, सांसद, समाजसेवी और सेवानिवृत्त खुफियातंत्र के खुराफाती लोग करते हैं ताकि वह देश दबाव में रहे। भारत को भी ब्लैकमेल करने के लिए ही शरजील इमाम के मौलिक अधिकारों का बहाना बनाकर भारत के लोकतंत्र की सेक्यूलर छवि को धूमिल करने की शरारत की गई है।

न्यूयॉर्क फेड से दोबारा निर्वाचित हुए अरविंद कृष्णा, दिसंबर 2029 तक संभालेंगे कार्यभार

(जीएनएस)।

वाशिंगटन(जीएनएस)। भारतीय-अमेरिकी टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव अरविंद कृष्णा को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में फिर से चुना गया है। उनका यह नया कार्यकाल तीन साल का होगा, जो दिसंबर 2029 तक चलेगा। आईबीएम के चेयरमैन, प्रेसिडेंट और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) कृष्णा, क्लास बी निदेशक के तौर पर अपना काम जारी रखेंगे। न्यूयॉर्क फेड ने शुक्रवार (स्थानीय समय) को बताया कि यह पद आम जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए होता है। उन्हें रिजर्व बैंक के ग्रुप 3 के सदस्य बैंकों द्वारा चुना गया था। यह ग्रुप सेकंड फेडरल रिजर्व डिस्ट्रिक्ट के छोटे बैंकों की एक श्रेणी है। उनका नया कार्यकाल 31 दिसंबर, 2029 को समाप्त होगा।

कृष्णा 2022 से न्यूयॉर्क फेड के बोर्ड में शामिल हैं। तब उन्हें एक अधूरे कार्यकाल को पूरा करने के लिए चुना गया था। इसके बाद 2023 में उन्हें फिर से चुना गया, जिसका कार्यकाल इस साल खत्म हो रहा है।

इस नए चुनाव के बाद, आईआईटी कानपुर से पढ़े कृष्णा उस बोर्ड में बने रहेंगे, जो क्षेत्रीय रिजर्व बैंक को केंद्रीय बैंक के बाहर के नजरिए से अवगत कराता है। इसमें अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे कि व्यापार और अन्य सेक्टरों के विचार शामिल होते हैं।

न्यूयॉर्क फेड के अनुसार, क्लास बी डायरेक्टर आम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें कृषि,



वाणिज्य, उद्योग, सेवा क्षेत्र, श्रम और उपभोक्ताओं जैसे विभिन्न हितों का ध्यान रखा जाता है।

न्यूयॉर्क फेड का बोर्ड, वाशिंगटन स्थित फेडरल रिजर्व बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से अलग है। क्षेत्रीय बैंक के बोर्ड में होने का मतलब यह नहीं है कि कृष्णा फेडरल ओपन मार्केट कमिटी (एफओएमसी) के सदस्य हैं; यह कमिटी ही अमेरिका की मौद्रिक नीति तय करती है।

कृष्णा अप्रैल 2020 में आईबीएम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने। कंपनी में तीन दशकों से ज्यादा के अपने करियर के दौरान, उन्होंने रिसर्च, क्लाउड कंप्यूटिंग और सॉफ्टवेयर जैसे क्षेत्रों में वरिष्ठ पदों पर काम किया है।

सीईओ बनने से पहले, वह क्लाउड और कॉग्निटिव सॉफ्टवेयर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, जहां उन्होंने आईबीएम के हाइब्रिड क्लाउड बिजनेस को बढ़ाने में योगदान दिया। न्यूयॉर्क फेड के अनुसार, उन्होंने आईबीएम रिसर्च का भी नेतृत्व किया, जहां उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और क्लाउड सेवाओं जैसे क्षेत्रों में काम की देखरेख की।

कृष्णा ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर से स्नातक की डिग्री और यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनोइस अबार्ना-शैंपेन से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। बैंक ने बताया कि वह नॉर्थरोप ग्रुम्मन और यूएस-इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम के बोर्ड में भी शामिल हैं।

12 क्षेत्रीय फेडरल रिजर्व बैंकों में से प्रत्येक के पास नौ सदस्यों वाला एक बोर्ड होता है। इन डायरेक्टर्स को तीन वर्गों में बांटा गया है: क्लास ए सदस्य बैंकों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि क्लास बी और क्लास सी आम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्षेत्रीय बैंक बोर्ड अपने जिलों की स्थितियों के बारे में दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। न्यूयॉर्क फेड के अध्यक्ष, अपने निदेशक मंडल से अलग, फेडरल ओपन मार्केट कमिटी के स्थायी वोटिंग सदस्य होते हैं।

यूएस एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए 50 अरब डॉलर की जरूरत : मंत्री डफी

(जीएनएस)।

अमेरिका, अमेरिका में देशव्यापी हवाई सेवा ठप होने का असर हजारों यात्रियों पर पड़ा। इसके बाद परिवहन मंत्री शॉन डफी ने हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए कांग्रेस से 50 अरब डॉलर की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने की मांग की है। डफी ने देर रात आयोजित प्रेस ब्रीफिंग में कहा, हवाई यातायात नियंत्रण केंद्रों में इस्तेमाल हो रहे पुराने संचार उपकरणों पर अत्यधिक दबाव पड़ने के कारण रडार और संचार संबंधी आंकड़ों में गड़बड़ी पैदा हुई। हालांकि, अधिकारियों ने स्पष्ट नहीं किया है कि तकनीकी खराबी की असल वजह क्या रही। शुक्रवार शाम को देशव्यापी उड़ान रोक हटा ली गई, लेकिन डफी ने आगाह किया कि उड़ान सेवाएं तत्काल सामान्य नहीं हो पाएंगी। एयरलाइंस को यह देखना होगा कि विमानों के संचालन के लिए पायलट और केबिन क्रू उपलब्ध हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि कुछ यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अगले दिन तक इंतजार करना पड़ सकता है।

अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) के कमांड सेंटर ने शुक्रवार रात 8:19 बजे (स्थानीय समय) देशव्यापी उड़ान रोक समाप्त करने का नोटिस जारी किया।

डफी के मुताबिक, यह व्यवधान दोपहर करीब 3:36 बजे शुरू हुआ, जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटरों और टर्मिनल रडार अप्रोच कंट्रोल (ट्रैकॉन) सुविधाओं में रडार तथा संचार प्रणाली अस्थिर हो गई।



उन्होंने बताया कि जिस समय तकनीकी समस्या सामने आई, उस समय 3,500 से अधिक विमान आसमान में थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों और पायलटों ने निर्धारित सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करते हुए विमानों को सुरक्षित नीचे उतारा। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि रडार और संचार व्यवस्था पूरी तरह ठप नहीं हुई थी।

डफी ने कहा कि आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं, ऑर्गन ट्रांसपोर्ट और कानून प्रवर्तन से जुड़ी उड़ानों को जारी रखने की अनुमति दी गई थी।

इस बीच, होमलैंड सिक्योरिटी मंत्री मार्कवेन मुलिन ने कहा कि शुरूआती जांच में साइबर हमले का कोई सबूत नहीं मिला है। हालांकि, जांच जारी है और किसी भी संभावना को खारिज नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस घटना का माइक्रोसॉफ्ट की अलग तकनीकी समस्या से कोई संबंध नहीं था।

डफी ने शुरूआती तौर पर समस्या के लिए पुराने स्विच और राउटर को जिम्मेदार बताया, जिनके माध्यम से दूरसंचार संबंधी आंकड़ों का आदान-प्रदान होता है। उन्होंने कहा, नए उपकरणों में ऐसी खराबी सामने नहीं आई है। अधिकारियों ने सिस्टम पर बढ़े दबाव को कम कर प्रभावित केंद्रों को दोबारा ऑनलाइन कर दिया।

यह पूछे जाने पर कि क्या एफएए की ओर से किसी सिस्टम में पैच लगाने के काम के कारण यह व्यवधान पैदा हुआ, डफी ने इससे इनकार किया। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि जांच अभी जारी है और वह खराबी की वजह को लेकर कोई ऐसी जानकारी नहीं देना चाहते जो बाद में गलत साबित हो।

परिवहन मंत्री ने बताया कि कांग्रेस पहले ही हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 12.5 अरब डॉलर की राशि मंजूर कर चुकी है, लेकिन व्यापक बदलाव की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त धन की जरूरत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि 50 अरब डॉलर की मांग अभी प्रस्ताव है, इसे कांग्रेस की मंजूरी नहीं मिली है।

डफी ने चेतावनी दी कि पुरानी तकनीक को पूरी तरह बदलने में समय लगेगा और जब तक मौजूदा उपकरण इस्तेमाल में रहेंगे, तब तक इस तरह की तकनीकी खराबी की आशंका बनी रहेगी।

उन्होंने उम्मीद जताई कि थैंक्सगिविंग के व्यस्त यात्रा सीजन के नजदीक आने तक हवाई सेवाएं सामान्य रूप से संचालित होने लगेंगी।

डफी ने यात्रियों को सलाह दी कि वे अपनी उड़ानों की ताजा स्थिति जानने के लिए संबंधित एयरलाइंस से संपर्क करें, क्योंकि कंपनियां व्यवधान के बाद उड़ानों का संचालन सामान्य करने में जुटी हैं।

दिलजीत दोसांझ के अहमदाबाद कॉन्सर्ट पर नई पाबंदियों की मांग, पटियाला पेग समेत 4 गाने नहीं गाने को कहा

(जीएनएस)।

पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। गुजरात के अहमदाबाद में 21 नवंबर को होने वाले उनके लाइव कॉन्सर्ट से पहले जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर कई पाबंदियां लगाने की मांग की है। अधिकारी ने दिलजीत से शराब, नशे और हिंसा को बढ़ावा देने वाले चार गाने नहीं गाने को कहा है। इसके अलावा कॉन्सर्ट में तेज आवाज, चमकती लाइटों और बच्चों को स्टेज पर बुलाने को लेकर भी चिंता जताई गई है। पुलिस कमिश्नर को लिखे पत्र में चार गानों का खास तौर पर जिक्र किया गया है। इनमें पटियाला पेग, 5 तारा ठेके, जेब विचो फीम और जट्ट फायर करदा शामिल हैं। बाल संरक्षण अधिकारी का कहना है कि इन गानों के बोल में शराब, अफीम, नशे और हथियारों का जिक्र है, जिसका बच्चों और युवाओं पर गलत असर पड़ सकता है। इन गानों को बदले हुए बोल के साथ भी नहीं गाया जाना चाहिए।



वहीं, दिलजीत 15 नवंबर को इंदौर में भी परफॉर्म करने वाले हैं। उनके इस कॉन्सर्ट से पहले शहर में तीन बैंकों और मेयर सेक्रेटेरिएट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई है। ईमेल पंजाबी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में लिखे गए हैं।

धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। जिन जगहों को निशाना बनाने की बात कही गई है, वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मेयर सेक्रेटेरिएट की बम डिस्पोजल स्क्वॉड ने पूरी तलाशी ली। टीम ने सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की।

जानकारी के मुताबिक, धमकी भरे ईमेल में बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और इंदौर के मेयर सचिवालय को निशाना बनाने की बात कही गई है। ईमेल मिलने के बाद बम डिस्पोजल स्क्वॉड की टीम मेयर सेक्रेटेरिएट पहुंची और परिसर की बारीकी से जांच की।

इस मामले पर इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि कुछ लोग अच्छे कामों में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसी धमकियों से कुछ हासिल नहीं होगा। इस तरह की धमकियों से शहर में होने वाले कार्यक्रमों और विकास से जुड़े कामों पर असर नहीं पड़ेगा।

वहीं, पुलिस अधिकारी राजेश दंडोतिया ने बताया कि चार अलग-अलग जगहों को निशाना बनाकर ईमेल के जरिए धमकियां दी गई हैं। पुलिस इन ईमेल की जांच कर रही है और उन्हें भेजने के लिए इस्तेमाल की गई ईमेल आईडी का पता लगाया जा रहा है। साथ ही यह भी जानने की कोशिश की जा रही है कि ये धमकी भरे संदेश कहां से भेजे गए और इनके पीछे कौन लोग हैं।

कॉस्मेटिक सर्जरी पर श्रुति हासन का बेबाक बयान, शराब की लत पर कहा- आठ साल तक नहीं पी एक बूंद

(जीएनएस)।

अभिनेत्री श्रुति हासन ने कॉस्मेटिक सर्जरी और शराब को लेकर अपने निजी अनुभवों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें कॉस्मेटिक प्रोसीजर के बारे में झूठ बोलने की कोई जरूरत महसूस नहीं होती। इसके साथ ही अभिनेत्री ने बताया कि वह आठ साल तक शराब से पूरी तरह दूर रही थीं। श्रुति हासन ने ये बातें नेहा धूपिया और अंगद बेदी के शो डबल डेट में बातचीत के दौरान कही। कॉस्मेटिक प्रोसीजर को लेकर अपनी राय रखते हुए उन्होंने कहा कि हर किसी को अपनी मर्जी से फैसले लेने का अधिकार है, लेकिन उन्हें इन फैसलों को छिपाने या उनके बारे में झूठ बोलने की जरूरत समझ नहीं आती।

श्रुति ने कहा, मैं इन चीजों के बारे में बहुत सोच-समझकर बात करती



हूं, लेकिन मैं लोगों के सामने बड़ी हुई हूं और ऐसे में इस बारे में झूठ बोलना बेवकूफी होगी। मैं किसी को जज नहीं कर रही हूं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं- मैं तो ऐसी ही पैदा हुई थी... जबकि तीन हफ्ते पहले तो आप ऐसे नहीं दिखते थे।

उन्होंने आगे कहा कि हर किसी की अपनी पसंद और अपनी जिंदगी है। किसी को भी अपने शरीर के साथ क्या करना है, यह तय करने का पूरा अधिकार है। उन्हें सिर्फ इस बात से परेशानी है कि लोग अपनी पसंद के बारे में सच बोलने से क्यों बचते हैं।

अभिनेत्री ने कहा, सबकी मर्जी, खुद की मर्जी। मुझे इसके बारे में झूठ बोलने की कोई वजह समझ नहीं आती। लेकिन मैं इसे बढ़ावा भी नहीं देना चाहती।

बातचीत के दौरान श्रुति ने अपनी जिंदगी के एक निजी पहलू पर भी बात की। उन्होंने शराब के साथ अपने रिश्ते और उससे दूरी बनाने के अनुभव को साझा किया। अभिनेत्री ने बताया कि वह लगातार आठ साल तक शराब से पूरी तरह दूर रही थीं। इस दौरान उन्होंने एक बूंद भी शराब नहीं पी थी। हालांकि, इसके बाद उन्होंने दोबारा शराब पीना शुरू कर दिया।

अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए श्रुति ने कहा, मैंने हमेशा खुलकर कहा है कि शराब मेरे लिए अच्छी नहीं है। अब मैं इसे लेकर बहुत सावधान रहती हूं। फिलहाल मैं इसे संभालने की कोशिश के सफर में हूं।

श्रुति हासन दिग्गज अभिनेता कमल हासन और अभिनेत्री सारिका ठाकुर की बेटी हैं। उन्होंने अपने करियर में हिंदी के साथ तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी काम किया है। अभिनय के अलावा वह संगीत में भी रुचि रखती हैं और एक गायिका के तौर पर भी अपनी पहचान बना चुकी हैं।

दिल्ली क्राइम सीजन 3 को 1 साल पूरा, रसिका दुग्गल बोलीं- ये शो मेरे दिल के बेहद करीब है

(जीएनएस)।

बॉलीवुड एक्ट्रेस रसिका दुग्गल की क्राइम-ड्रामा वेब सीरीज दिल्ली क्राइम सीजन-3 ने अपनी रिलीज के एक साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर अभिनेत्री ने सीरीज को लेकर बताया कि यह उनके दिल के बेहद करीब है। उन्होंने कहा, दिल्ली क्राइम के जरिए मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि कहानी हमारी असल जिंदगी से जुड़ी है। अगर कहानियों को सच्चाई और ईमानदारी से दिखाया जाए, तो वो देश की सरहदें पार करके दुनियाभर के लोगों से जुड़ सकती हैं। शो को जो प्यार और सम्मान मिला है, जिसमें इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड भी शामिल है, वो मेरे लिए बहुत हौसला बढ़ाने वाला रहा है। सीजन 3 के एक साल बाद, मैं बहुत खुश और आभारी हूं कि मैं तीनों सीजन का हिस्सा रही और मैंने नीति सिंह को हर सीजन में आगे बढ़ते हुए देखा। उन्होंने आगे कहा, मुझे दिल्ली क्राइम की टीम के साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है। ये सभी बहुत खास और अच्छे लोग हैं। मुझे उम्मीद है कि हम आगे भी साथ में काम करते रहेंगे।



वेब सीरीज दिल्ली क्राइम सीजन 3 में रसिका दुग्गल ने पुलिस अधिकारी नीति सिंह का दमदार किरदार निभाया था। उनके इस सीजन के सफर में एक कठिन और पेचीदा मामले के साथ-साथ उनके निजी जीवन के संघर्ष और ट्रॉमा को भी बहुत खूबसूरती से दिखाया गया था।

यह सीजन मुख्य रूप से मानव तस्करी और महिला/बाल तस्करी के एक बड़े और खतरनाक रैकेट पर आधारित है। कहानी की शुरूआत असम में एक ट्रक और उससे जुड़े मामलों की छानबीन से होती है, जो बाद में दिल्ली और देश के कई अन्य हिस्सों से जुड़े एक बड़े नेटवर्क का पदार्फाश करती है। इसमें हुमा कुरैशी के अभिनय को भी काफी सराहा गया है।

यह सीरीज भावनात्मक रूप से झकझोर देने वाली और पुलिस की जांच पर आधारित एक बेहतरीन सस्पेंस थ्रिलर है। इस क्राइम-थ्रिलर सीरीज का निर्देशन तनुज चोपड़ा ने किया है। सीरीज में रसिका के साथ-साथ शेफाली शाह (डीआईजी वर्तिका चतुर्वेदी), हुमा कुरैशी (खतरनाक विलेन बड़ी दीदी), राजेश तैलंग और सयानी गुप्ता अहम भूमिकाओं में हैं।

करियर की शुरूआत में डबल रोल निभाने में क्या आई चुनौती, शनाया कपूर ने बताया

(जीएनएस)।

अभिनेत्री शनाया कपूर ने स्टूडेंट ऑफ द ईयरः आफ्टर डार्क सीरीज में अपने करियर की शुरूआत में ही डबल रोल निभाने की चुनौतियों के बारे में बताया। अभिनेत्री ने अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए बताया कि इस प्रोजेक्ट ने उन्हें अपनी एक्टिंग की क्षमताओं को और बेहतर ढंग से परखने का मौका दिया, जबकि शूटिंग के दौरान उन्हें कई मुश्किल चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। शनाया ने सोशल मीडिया पर फिल्म निमार्ता करण जौहर को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उन्हें डबल रोल निभाने का मौका दिया, जिससे उन्हें अपनी एक्टिंग के अलग-अलग पहलुओं को दिखाने का अवसर मिला। अभिनेत्री ने निर्देशक रीमा सेन का भी आभार जताया, जिन्होंने उन्हें अपने क्रिएटिव सुझाव साझा करने की पूरी छूट दी।

शनाया ने उन मुश्किल एक्शन और अंडरवॉटर सीन्स के बारे में भी बताया, जिन्हें करना उनकी सोच से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण था। उन्होंने मुश्किल पलों में मार्गदर्शन और सहयोग देने के लिए एक्शन टीम और अंडरवॉटर टीम को धन्यवाद दिया। अभिनेत्री ने कहा कि शूटिंग के दौरान कुछ दिन बहुत कठिन थे, लेकिन उनके आसपास मौजूद लोगों के भरोसे और समर्थन ने उन्हें इन चुनौतियों से पार पाने में मदद की।



सेट से कुछ बिहाइंड-द-सीन्स (पर्दे के पीछे की) तस्वीरें साझा करते हुए आंखों की गुस्ताखियां फेम अभिनेत्री ने लिखा, यह शो मेरे लिए सब कुछ है, और यह पूरी शानदार, बेहतरीन और कमाल की टीम के बिना मुमकिन नहीं हो पाता। मैं करण जौहर को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने मुझे इतनी खास फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाने का मौका दिया। मेरे करियर की शुरूआत में ही मुझे डबल रोल निभाने का अवसर मिला, जिससे मैं एक अभिनेत्री के तौर पर अपनी रेंज दिखा सकी। मुझ पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि मैं आपको गौरवान्वित कर पाऊंगी।

उन्होंने कहा कि एक्शन डायरेक्टर बंटी सर से लेकर सुकेश सर नेतृत्व वाली टीम तक आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे उन सीमाओं से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, जहां तक पहुंचने के बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कुछ दिन बहुत मुश्किल थे, और अगर आप लोगों को मुझ पर भरोसा न होता, तो मैं इनमें से कुछ भी नहीं कर पाती। सबसे चुनौतीपूर्ण अंडरवॉटर शॉट्स के दौरान आपने मेरा हाथ थामे रखा। धन्यवाद।

उन्होंने आगे कहा, पूरी क्रू टीम का धन्यवाद—इस सीरीज की शूटिंग करना काफी चुनौतीपूर्ण था, और मुझे पता है कि हर दिन, हर मिनट और हर सेकंड बहुत अहम था। आप सभी के बिना यह मुमकिन नहीं हो पाता।

शनाया ने सभी से शो देखने की अपील की और लिखा, कृपया कल जियोहॉटस्टार पर हमारा शो 'स्टूडेंट ऑफ द ईयरः आफ्टर डार्कइ जरूर देखें। इसे आप लोगों के लिए बहुत मेहनत, खून-पसीना और आंसुओं (सचमुच!) के साथ बनाया गया है। आप सभी को बहुत प्यार।

स्टूडेंट ऑफ द ईयरः आफ्टर डार्क 2012 की कैंपस-रोमांस फ्रेंचाइजी को एक सस्पेंस से भरी मर्डर मिस्ट्री के रूप में पेश करती है। इस सीरीज के साथ शनाया कपूर ओटीटी (ओटीटी) पर डेब्यू कर रही हैं, जिसमें वह जुड़वां बहन आयशा और अदिति मलिक के डबल रोल में नजर आएंगी।

करण जौहर द्वारा प्रोड्यूस की गई यह हिंदी थ्रिलर सीरीज 13 नवंबर को जियोहॉटस्टार पर रिलीज होगी।

PRGI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M) 9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

तहसील बारा को मिला आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन, प्रशासनिक व्यवस्था को मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान

(जीएनएस)।

लखनऊ /प्रयागराज

तहसील बारा को मिला आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन, प्रशासनिक व्यवस्था को मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान, आईएएस अर्पित कुमार की मेहनत लाई रंग बेहतर आधारभूत सुविधाओं, अभिलेखों के डिजिटलीकरण और पारदर्शी कार्यप्रणाली का मिला लाभ, डीएम के मार्गदर्शन में एसडीएम अर्पित कुमार की पहल रंग लाई

प्रयागराज। तहसील बारा ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सुधार और बेहतर जनसेवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। तहसील को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए क्रड 9001:2015 प्रमाणन प्राप्त हुआ है। इससे तहसील की कार्यशैली, व्यवस्थाओं में सुधार और अभिलेखों के सुव्यवस्थित रखरखाव को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। यह उपलब्धि प्रयागराज जिले के लिए भी गौरव का विषय है।



इस उपलब्धि के पीछे तहसील में आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने, सरकारी अभिलेखों को व्यवस्थित करने, रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण करने तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए किए गए प्रयास शामिल हैं। इन सुधारों का उद्देश्य आम जनता को बेहतर, सुगम और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना है।

जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के मार्गदर्शन और नेतृत्व में एसडीएम एवं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बारा आईएएस अर्पित कुमार ने इस दिशा में विशेष पहल की। उन्होंने तहसील की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया। इसमें तहसील के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी महत्वपूर्ण सहयोग दिया। पूरी टीम ने मिलकर कार्यालय की कार्यप्रणाली को व्यवस्थित करने और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए।

आईएसओ प्रमाण मिलने से तहसील प्रशासन की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। अब निर्धारित गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना और उनमें लगातार सुधार करना महत्वपूर्ण होगा। इस उपलब्धि पर अधिकारियों और कर्मचारियों में उत्साह है। प्रशासनिक स्तर पर तहसील की पूरी टीम के प्रयासों की सराहना की जा रही है।

कोडीनयुक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार पर शिकंजे की तैयारी, एफएसडीए ने केंद्र को भेजे छह बड़े सुझाव

(जीएनएस)।

लखनऊ, नशे के रूप में इस्तेमाल हो रहे कोडीनयुक्त कफ सिरप के अवैध कारोबार और उसकी गैर-चिकित्सकीय आपूर्ति पर रोक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) ने दवा वितरण व्यवस्था को सख्त बनाने की पहल की है। विभाग ने केंद्र सरकार को छह प्रमुख नियामकीय सुझाव भेजते हुए निमार्ताओं से लेकर थोक विक्रेताओं तक पूरी आपूर्ति व्यवस्था की निगरानी मजबूत करने की मांग की है। विभाग का उद्देश्य दवा के अवैध डायवर्जन पर रोक लगाने के साथ ही वास्तविक मरीजों के लिए इसकी चिकित्सकीय उपलब्धता बनाए रखना है।एफएसडीए की सचिव एवं आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने केंद्रीय मंत्रालय को रिमाइंडर भेजकर प्रस्तावों पर शीघ्र निर्णय लेने और जरूरी दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। विभाग की जांच में सामने आया कि कोडीनयुक्त कफ सिरप की बड़ी मात्रा की बिलिंग तो की जा रही थी, लेकिन उसके अनुरूप दवाएं अधिकृत खुदरा बाजार तक नहीं पहुंच रही थीं। कई मामलों में खरीद-बिक्री के दस्तावेजों और वास्तविक भौतिक स्टॉक में भी अंतर मिला। इससे दवाओं के चिकित्सकीय उपयोग के बजाय नशे के लिए इस्तेमाल और अवैध कारोबार में पहुंचने की आशंका गहराई।प्रदेश में कोडीनयुक्त कफ सिरप के निर्माण और आपूर्ति को लेकर की गई अंतरराज्यीय जांच में समानांतर वितरण नेटवर्क के संकेत मिले। रांची, हिमाचल प्रदेश और अन्य बाहरी मार्गों से आने वाले उत्पादों की वास्तविक आवाजाही और उनके अंतिम गंतव्य का पता लगाने में भी कठिनाइयां सामने आईं। जांच के दौरान विभाग ने 52 जिलों में 332 थोक दवा प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर अभिलेखों का सत्यापन किया। गंभीर अनियमितताएं मिलने पर 36 जिलों की 161 फर्मों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और एनडीपीएस अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज कराए गए। इनके लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई भी शुरू की गई है।विभाग ने केंद्र को सुझाव दिया है कि कोडीनयुक्त कफ सिरप बनाने वाली कंपनियां अपने उत्पादों की आपूर्ति केवल अधिकृत सीएफए और उत्तर प्रदेश में स्थापित वैध स्टॉकिस्टों के माध्यम से करें। जांच में कुछ कंपनियों की ओर से सामान्य वितरण व्यवस्था से अलग स्टॉकिस्ट नियुक्त किए जाने की बात सामने आई थी। इनमें कई उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित थे और इनके जरिए प्रदेश के थोक कारोबारियों को बड़ी खेप की बिलिंग की जा रही थी। विभाग का मानना है कि केवल कोडीनयुक्त उत्पादों के लिए अलग समानांतर वितरण चैनल बनाने पर रोक लगने से प्रत्येक खेप की जवाबदेही तय की जा सकेगी।दूसरे महत्वपूर्ण प्रस्ताव में प्रदेश की वास्तविक चिकित्सकीय जरूरत के आधार पर सिरप की आपूर्ति निर्धारित करने की बात कही गई है। इसके लिए पिछले वर्षों की खपत, मरीजों की जरूरत और बाजार की वास्तविक मांग का वैज्ञानिक आकलन किया जाए। इसके बाद कंपनियां अपने प्रदेश स्थित अधिकृत सीएफए और वहां से लाइसेंसधारी थोक विक्रेताओं को पारदर्शी तरीके से दवा उपलब्ध कराएं। इससे जरूरत से अधिक भंडारण और दवाओं के अवैध इस्तेमाल की आशंका कम होगी।एफएसडीए ने यह भी सुझाव दिया है कि निमार्ता कंपनियां कोडीनयुक्त कफ सिरप और अन्य नियंत्रित दवाओं की खेप भेजने से पहले संबंधित राज्य के औषधि नियंत्रक को अनिवार्य रूप से सूचना दें। इस सूचना में दवा की मात्रा, बैच, आपूर्तिकर्ता और गंतव्य का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही थोक से थोक बिक्री पर रोक लगाने और आपूर्ति को अधिकृत वितरण व्यवस्था के माध्यम से खुदरा स्तर तक पहुंचाने की व्यवस्था लागू करने की पैरवी की गई है।दवाओं की आवाजाही पर नजर रखने के लिए टीबी की दवाओं की तर्ज पर क्यूआर कोड और बारकोड आधारित डिजिटल ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव भी भेजा गया है। इसके तहत प्रत्येक बैच की रिपोर्टिंग, वास्तविक समय में निगरानी और जोखिम के आधार पर अलर्ट जारी करने की व्यवस्था विकसित करने की बात कही गई है। इससे निमार्ता से लेकर अंतिम बिक्री तक दवा की प्रत्येक खेप का पता लगाया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त अधिक दुरुपयोग की आशंका वाली दवाओं के लिए अलग शेड्यूल एच-3 बनाने और राज्यों में वास्तविक खपत के आधार पर भंडारण की सीमा निर्धारित करने का सुझाव दिया गया है।विभाग ने स्पष्ट किया है कि कोडीनयुक्त कफ सिरप पूरी तरह प्रतिबंधित या नकली दवा नहीं है, बल्कि यह मान्य चिकित्सकीय औषधि है। इसका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह पर गंभीर खांसी और अन्य निर्धारित उपचार संबंधी जरूरतों में किया जाता है। इसलिए इसका उद्देश्य वैध चिकित्सा उपयोग को प्रभावित करना नहीं, बल्कि नशे के लिए होने वाली अवैध आपूर्ति और बड़े पैमाने पर डायवर्जन को रोकना है। जांच में सीमावर्ती जिलों के साथ नेपाल और बांग्लादेश की ओर कथित अवैध आपूर्ति को लेकर भी चिंता सामने आई है। एफएसडीए चाहता है कि अवैध कारोबार पर प्रभावी रोक लगे और जरूरतमंद मरीजों को अधिकृत मेडिकल स्टोर पर उनकी आवश्यकता के अनुसार दवा

प्रयागराज के एमएलएन मेडिकल कॉलेज में एनाटामी विभाग के मोर्चरी में 'डकैती', बदमाशों ने लाखों रुपये का सामान उड़ाया

(जीएनएस)।

लखनऊ/प्रयागराज

प्रयागराज शहर में बदमाशों का आतंक बढ़ गया है। इस बार किसी मकान को नहीं बल्कि सरकारी मोती लाल नेहरू (टछठ) मेडिकल कॉलेज को निशाना बनाया है। बदमाशों ने मेडिकल कॉजेज के एनाटामी विभाग के मोर्चरी में डाका डाला और लाखों रुपये का कीमती सामान उड़ा दिया है।

मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा-व्यवस्था पर उठे सवाल

घटना की जानकारी होने पर विभागाध्यक्ष कृष्णा पांडेय की तहरीर पर जार्जटाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, लेकिन अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा-व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। एटानामी विभाग के डॉक्टर बादल सिंह का कहना है कि बदमाशों ने डाका डाला और इत्मिनान से पांच कमरों के पंखे खोले, उपकरण निकाले, डीप फ्रीजर, कूलिंग प्लांट, शव वाहन समेत लाखों रुपये का सामान गायब कर दिया।

सात से 11 नवंबर के बीच हुई घटना

बताया गया है कि दीपावली के दौरान मेडिकल कॉलेज के एनाटामी विभाग में अवकाश था। इसी दौरान रात में कई बदमाश पहुंचे और मोर्चरी में दाखिल हो गए। बदमाशों ने निडर होकर इलेक्टानिक वायरिंग, कूलिंग प्लांट, शव वाहन, बैट्री, एग्जास्ट फैन, आरा मशीन, पंखा, मोटर गायब किया। साथ ही एसी के कंप्रेशर निकाला। इलेक्ट्रानिक उपकरणों में तोड़फोड़ भी की। सात से 11 नवंबर के बीच हुई घटना की जानकारी शुक्रवार को तब हुई जब मोर्चरी को खोला गया। वहां की हालत देख स्वास्थ्य कर्मी परेशान हो गए। खबर पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और छानबीन की। इसके बाद तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया।



लाखों रुपये का सामान बाहर कैसे निकाला गया?

कहा गया है कि घटना स्थल पर सीसीटीवी नहीं लगा है। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि लाखों रुपये का सामान बाहर कैसे निकाला गया। ऐसा तब हुआ जब मेडिकल कॉलेज के गेट पर निजी सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती रहती है। बहरहाल, इस घटना से डॉक्टरों, विद्यार्थियों का कार्य भी प्रभावित हो रहा है।

लाइसेंसी बंदूक, रायफल का भी नहीं लगा सुराग

कुछ दिन पहले जेल में बंद हत्यारोपित वकील देवेंद्र नाथ मिश्रा के घर से चोरों ने नकदी, जेवरात के साथ लाइसेंसी बंदूक, रायफल गायब कर दिया था। देवेंद्र के भाई की तहरीर पर कर्नलगंज पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज किया, लेकिन अब तक किसी असलहे को बरामद नहीं कर सकी है। उनके दुरुपयोग की संभावना बढ़ गई है, मगर पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली है।

बढ़ती घटनाओं से लोगों में खौफ

चोरी, छिनैती, लूट की बढ़ती घटनाओं से लोगों में खौफ पैदा होने लगा है। अपराध में बढ़ोतरी तब हुई है, जब सहालग का दौर शुरू हो गया है। तमाम लोगों के घरों में शादी को लेकर तैयारी चल रही है, लेकिन परिवार के मुखिया के मन में चोरी का डर सता रहा है। पुलिस अधिकारी भले ही अपराधियों पर सख्त कार्रवाई का दावा कर रहे हैं, पर आमजन में भरोसा मजबूत नहीं बना पा रहे।

साइबर ठगी के शिकार लोगों को पुलिस ने वापस कराए 1.11 लाख रुपये, आठ मामलों में मिली सफलता

बीसलपुर और अमरिया थाना क्षेत्र की साइबर टीमों ने की कार्रवाई, पीड़ितों के खातों में वापस कराई ठगी की रकम।

(जीएनएस)।

पीलीभीत। साइबर अपराध के जरिए लोगों से ठगी गई रकम वापस दिलाने के लिए पीलीभीत पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में बीसलपुर और अमरिया थाना क्षेत्र की साइबर टीमों ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए आठ अलग-अलग मामलों में पीड़ितों की कुल 1,11,519.03 रुपये की धनराशि वापस कराई है।

पुलिस अधीक्षक पीलीभीत के निर्देश पर जनपद के थानों में स्थापित साइबर हेल्प डेस्क के माध्यम से साइबर अपराध से पीड़ित लोगों की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। इसी अभियान के तहत बीसलपुर और अमरिया थाने की साइबर टीमों ने संबंधित बैंकों, एमआरएम पोर्टल और माननीय न्यायालय के आदेशों के माध्यम से ठगी की रकम वापस कराने में सफलता हासिल की।

पुलिस के अनुसार, बीसलपुर थाना क्षेत्र के चार मामलों में पीड़ितों को कुल 35,024.08 रुपये वापस कराए गए। वहीं अमरिया थाना क्षेत्र के चार मामलों में 76,494.95 रुपये की धनराशि पीड़ितों के खातों में वापस कराई गई।

इन मामलों में किसी पीड़ित को 2,914.08 रुपये, किसी को 22 हजार रुपये, तो किसी को 13,477.95 रुपये और 53,497 रुपये की धनराशि वापस मिली। पुलिस ने संबंधित बैंकों से समन्वय स्थापित कर साइबर ठगी की रकम वापस कराने की प्रक्रिया पूरी की।

इस प्रकार दोनों थानों की साइबर टीमों ने कुल आठ मामलों में 1,11,519.03 रुपये की धनराशि पीड़ितों को वापस कराकर राहत पहुंचाई। पीलीभीत पुलिस ने साइबर अपराध से बचाव और पीड़ितों की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है।

एसआरएम 2.0 के तहत स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण, परखी व्यवस्थाएं

मुरादाबाद मंडल की उच्चस्तरीय टीम ने सीएचसी बीसलपुर और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का लिया जायजा

(जीएनएस)।

बीसलपुर । स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और बेहतर बनाने के उद्देश्य से एसआरएम 2.0 कार्यक्रम के तहत मुरादाबाद मंडल से आई उच्चस्तरीय टीम ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) बीसलपुर सहित क्षेत्र के विभिन्न आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का औचक निरीक्षण किया। टीम में उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. केके रंजन और डीसीपीएम प्रभात शामिल रहे।



निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने सीएचसी की ओपीडी सेवाओं, दवाओं की उपलब्धता और मरीजों को दी जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति परखी। इसके साथ ही अस्पताल के अभिलेखों, स्टॉक रजिस्टर और ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों का मिलान कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। टीम ने विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के संचालन की स्थिति भी देखी।

अधिकारियों ने संबंधित स्वास्थ्यकर्मियों को स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता बनाए रखने और व्यवस्थाओं में आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए। इसके अलावा क्षेत्र के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में उपलब्ध सुविधाओं और वहां संचालित स्वास्थ्य सेवाओं का भी जायजा लिया गया।

इस दौरान सीएचसी अधीक्षक डॉ. आलमगीर, बीसीएम सरफराज अहमद, बीपीएम प्रदीप गंगवार, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर एवं जिला मातृत्व स्वास्थ्य परामर्शदाता नितिन गंगवार सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे।

जनगणना-2027 को लेकर बीसलपुर ब्लॉक से निकाली गई जागरूकता रैली





'हमारी जनगणना, हमारा विकास' के नारे के साथ लोगों को स्व-गणना के प्रति किया जागरूक

(जीएनएस)।

पीलीभीत/बीसलपुर जनगणना-2027 के द्वितीय चरण को लेकर शनिवार को विकासखंड बीसलपुर से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को ब्लॉक परिसर से रवाना किया गया, जो बिलसंडा मार्ग की ओर गई और भ्रमण के बाद पुनः ब्लॉक परिसर में पहुंचकर संपन्न हुई। रैली के माध्यम से लोगों को जनगणना में भागीदारी करने और स्व-गणना के प्रति जागरूक किया गया।

रैली के दौरान 'हमारी जनगणना, हमारा विकास' और 'जनपद पीलीभीत को सबसे आगे ले जाना है' जैसे संदेशों के माध्यम से जनगणना के महत्व को बताया गया। अभियान के तहत स्व-गणना का कार्य 16 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक चलेगा। इस दौरान लोग अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से स्वयं अपना विवरण दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद जनसंख्या गणना का चरण एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 तक चलेगा, जिसमें घर-घर जाकर परिवारों से जानकारी एकत्र की जाएगी। जनवरी 2027 में पुनरीक्षण चरण के तहत दर्ज आंकड़ों की पुनः जांच एवं पुष्टि की जाएगी।

इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख अशोक शर्मा, एडीओ पंचायत कृष्णा देवी, प्रभारी एडीओ एसटी आरेंद्र गंगवार, वीडीओ सर्वेश कुमार, सचिव रेनू वर्मा, राहुल, संतोष, नूरुद्दीन, मुकेश राणा, सचिन सक्सेना और नवनीत कुमार सहित समस्त पंचायत सहायक, सफाई कर्मचारी तथा वीबी रामजी स्टाफ के कर्मचारी मौजूद रहे।

मसौली के धरौली और रहरामऊ में आस्था का महापर्व छठ धूमधाम से शुरू, आज अस्ताचलगामी सूर्य को दिया जाएगा पहला अर्ध्य

(जीएनएस)।

मसौली बाराबंकी। कार्तिक शुक्ल की षष्ठी को मनाया जाने वाला छठ त्यौहार का उत्तर भारत में बेहद महत्व है। रोशनी पर्व दीपावली के खत्म होते ही छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो जाती है जो सूर्य को समर्पित छठ पूजा बेहद स्वच्छता,नियम एव विधि विधान के साथ मनाया जाता है। जिसमे पुरुष एव स्त्री दोनों समान रूप से पूजा करते है।

उत्तर भारत में मनाये जाने वाले इस पर्व को क्षेत्र की ग्राम पंचायत धरौली के मजरे नईबस्ती एव ग्राम पंचायत रहरामऊ के मजरे बसन्तनगर में बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। दोनों गाँवो के निवासी पूर्व में बिहार के निकटवर्ती जिलो के रहने वाले हैं जिनमे छठ पर्व को लेकर बड़ी उत्सकता रहती है। नईबस्ती गांव के किनारे स्थित ड्रेन एव बसन्तनगर के किनारे स्थित गाड़ी नदी में छठ पूजा के दिन भारी भीड़ जमा होती है। लक्ष्मी पूजन के बाद से ही कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नहाय खाय का नियम होता है जिसका बड़े ही कड़ाई से पालन किया जाता हैं। व्रत रखने वाले पुरी शुद्धता के साथ बनाये हुए आहार का सेवन करते है शुक्ल पंचमी के दिन खरना पूजाविधि का पालन किया जाता है। सांयकाल के समय घाट पर पूरी शुद्धता से तैयार की गयी गुड़ दूध की खीर और पूड़ी एव फल का भोग छठ माता को लगाया जाता हैं तथा डूबते हुए सूरज को पहला अर्ध्य दिया जाता हैं इसके बाद इस प्रसाद को घर के सदस्यों में बांटा जाता है तथा रात भर घाट पर छठ मइया के गीत गाये जाते है। सप्तमी को सूर्योदय से पहले ब्रह्ममुहर्त में भगवान सूर्य के समक्ष घाट के तट पर अर्ध्य दिया जाता है। यहाँ पर सभी व्रती पुरुष-महिला पकवान, नारियल, और फलदान को लेकर घाट पर एकत्र होते है और उगते हुए सूरज की पूजा करते है। जिसको पारण कहा जाता हैं।



पर्व पर नए कपड़े पहन कर ही पूजा करने का रिवाज है खास बात यह है कि इस व्रत में व्रती महिलाएं डूबते सूर्य को अर्ध्य देकर छठ माता और भगवान सूर्य से पुत्रो की लम्बी आयु की कामना करते है। जिन महिलाओं के बच्चे नही होते है वो महिलाएं भी छठ मइया का व्रत रखती है जिससे उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। मान्यता यह भी है कि इस पर्व में लोग पूजा की सामग्रियों से भरी डलिया अपने सिर पर ही रखकर लाते है। आस्था के अनुसार सिर पर रखकर डलिया लाने वाले व्यक्ति की छठमैया हर मनोकामना पूरी करते है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि सूरज देव की शक्तियों का मुख्य आधर उनकी पत्नी ऊषा और प्रत्यूषा हैं। छठ में सूर्य के साथ-साथ दोनों शक्तियों की भी आराधना की जाती है। सुबह के अर्ध्य में सूर्य की पहली किरण यानी ऊषा और शाम के अर्ध्य में सूर्य की अंतिम किरण यानी प्रत्यूषा को अर्ध्य देकर दोनों से प्रार्थना की जाती है। माता उनकी सन्तानो की रक्षा और सबका कल्याण करती है।

(रविवार की शाम को पहला अर्ध्य व सोमवार की सुबह उगते हुए सुरज को दिया जायेगा अर्ध्य)

मंगलवार को डूबते हुए सुरज को छठ पूजा का पहला अर्ध्य पानी में खड़े होकर सूर्य देव को दिया जायेगा जिसमे बड़ी संख्या मे छठ व्रती अपने पूरे परिवार एवं गाजे-बाजे के साथ छठ घाट पर जाकर शाम को पूरे विधि-विधान से छठ व्रतियों ने डूबते सूर्य एवं छठ माता की आराधना करेंगी

जिसमे छठी व्रतियों ने गेहूं, घी व शक्कर का ठेकुआ, चावल, घी और शक्कर का लड्डू प्रसाद के लिए बना कर बांस के बने सूप डाला, दौरा, टोकरी में प्रसाद को रखकर घाट पहुंचेगी जहा रात्रि भर महिलाए घाट पर रहेंगी तथा मंगलवार को तड़के उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए छठ व्रती सूर्य उदय से पहले ही घाट पहुंचने लगेंगे। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद 36 घंटे का कठिन व्रत का पारण होगा।

शहाबपुर में भूमाफियाओं की दबंगईः नाला पाटे जाने से मुख्य मार्ग पर जलभराव, पंचायत भवन के सामने तालाब का पानी भरा'

(जीएनएस)।

मसौली बाराबंकी। कस्बा शहाबपुर स्थित महातलियाँ तालाब से जलनिकासी के लिए निकला नाला अवैध प्लाटिंग कारोबारियों की भेट चढ़ जाने से कस्बे को जाने वाला मुख्य मार्ग पर जलभराव की स्थित बन गयी है पंचायत भवन के सामने पक्की सड़क पर बिन बरसात के भरा पानी राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बन गया है।

बताते चले कि कस्बा शहाबपुर का जाने वाली पक्की सड़क पर वर्तमान मे भारी जलभराव होने के कारण लोगो को आवगमन मे दिक्कते हो रही है



पंचायत भवन के सामने सड़क पर भारी जलभराव की स्थित बनी हुई है लोगो के अनुसार बाजार के निकट स्थित

महातलियाँ तालाब से पानी जल निकासी के लिए नाला बना था जिसे अवैध प्लाटिंग करने वाले भूमाफियों ने नाले को कब्जे मे लेकर प्लाटिंग कर दी है जिससे तालाब का पानी नही निकल पा रहा है और तालाब का पानी सड़क तक पहुंच चुका है। उक्त स्थान के निकट उच्च प्राथमिक विद्यालय भी स्थित स्कूल जाने वाले बच्चे गंदे पानी से गुजर कर विद्यालय जाने को मजबूर हैं। कस्बा शहाबपुर निवासी गुलाम रसूल, बद्रदूजा, मो0 रफी, मो0 नफीस, मो0 शकील आदि ग्रामीणों ने जलनिकासी की मांग की है

लखनऊ विश्वविद्यालय को 72 लाख की अंतरराज्यीय शोध परियोजना, पांच राज्यों के 17 जिलों में होगा अध्ययन

(जीएनएस)।

लखनऊ, लखनऊ विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने विश्वविद्यालय को 71 लाख 92 हजार 500 रुपये की अंतरराज्यीय शोध परियोजना स्वीकृत की है। इस राशि पर जीएसटी अतिरिक्त देय होगा। परियोजना के तहत पांच राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति अधिकारों, संपत्ति अभिलेखों की स्वीकार्यता और उनके सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक प्रभावों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। इस शोध में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और मिजोरम के 17 जिलों के 85 गांवों के 3,150 परिवारों को शामिल किया जाएगा।विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, इस परियोजना को महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय रोजगार अध्ययन शोध पीठ के माध्यम से संचालित किया जाएगा। शोध पीठ के निदेशक प्रो. अनूप कुमार भारतीय परियोजना के मुख्य अन्वेषक होंगे। डॉ. ओमेंद्र कुमार यादव और डॉ. अनुपमा सिंह सह-अन्वेषक के रूप में अध्ययन में अपनी भूमिका निभाएंगे। परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्ति अधिकारों की वास्तविक स्थिति का आकलन करना और अलग-अलग राज्यों में लागू व्यवस्थाओं की तुलना कर नीतिगत सुझाव तैयार करना है।अब तक देश में इस तरह की व्यापक अंतरराज्यीय और तुलनात्मक शोध परियोजनाओं के संचालन में राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित शोध संस्थानों की प्रमुख भूमिका रही है। ऐसे में पंचायती राज मंत्रालय की ओर से उत्तर प्रदेश के एक राज्य विश्वविद्यालय को पांच राज्यों में विस्तृत अध्ययन की जिम्मेदारी दिया जाना विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। इससे विश्वविद्यालय की शोध क्षमता और राष्ट्रीय स्तर पर उसकी भूमिका को भी मजबूती मिलेगी।परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए कुलपति प्रो. जे.पी. सैनी के निर्देश पर कुलसचिव डॉ. भावना मिश्रा ने प्रशासनिक स्वीकृति पत्र जारी कर दिया है। विश्वविद्यालय ने पंचायती राज मंत्रालय की निर्धारित शर्तों के अनुरूप आवश्यक बंधपत्र भी निष्पादित कर मंत्रालय को भेज दिया है। कुलपति की मंशा विश्वविद्यालय की शोध पीठों को बाहरी वित्तपोषण से संचालित अनुसंधान, संस्थागत संसाधन सृजन और रोजगारोन्मुखी गतिविधियों के प्रभावी केंद्र के रूप में विकसित करने की है। इस परियोजना को इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।शोध परियोजना से राष्ट्रीय, राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर विशेषज्ञों तथा शोध कर्मियों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। इसके तहत करीब 55 अस्थायी परियोजना आधारित कार्य अवसर सृजित होने की संभावना है। इनमें एक राष्ट्रीय परामर्शदाता, निगरानी एवं मूल्यांकन तथा परिचालन विशेषज्ञ, दो राज्य स्तरीय परामर्शदाता, लगभग 50 शोध कर्मी एवं क्षेत्रीय अन्वेषक और दो प्रशासनिक एवं वित्तीय अभिलेख सहयोगी शामिल होंगे। इससे शोध कार्य के साथ-साथ विभिन्न स्तरों पर युवाओं और विशेषज्ञों को काम करने का अवसर मिलेगा।अध्ययन के दौरान ग्रामीण आवासीय संपत्तियों के स्वामित्व, संपत्ति कार्डों की कानूनी एवं संस्थागत स्वीकार्यता, संपत्ति विवादों और बैंकिंग तथा संस्थागत ऋण सुविधाओं तक ग्रामीण परिवारों की पहुंच का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके साथ ही वित्तीय समावेशन और ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली पर भी अध्ययन किया जाएगा। इसके लिए परिवारों का सर्वेक्षण, क्षेत्रीय जांच, समूह चर्चा, प्रमुख जानकारों के साक्षात्कार और संबंधित संस्थाओं के साथ परामर्श जैसी शोध पद्धतियां अपनाई जाएंगी।

प्रदेश के 26,720 परिषदीय विद्यालयों का होगा सोशल ऑडिट, छह माह में पूरी होगी प्रक्रिया

(जीएनएस)।

लखनऊ, प्रदेश की परिषदीय शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत प्रदेश के सभी 75 जिलों में संचालित परिषदीय विद्यालयों में से 20 प्रतिशत का सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) कराया जाएगा। इसके लिए कुल 26,720 विद्यालय चिह्नित किए गए हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से विद्यालयों में संचालित योजनाओं के वित्तीय और भौतिक कार्यों का स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाएगा, ताकि कमियों और अनियमितताओं की पहचान कर व्यवस्था में सुधार किया जा सके।सोशल ऑडिट कराने के लिए सोशल ऑडिट निदेशालय, ग्राम्य विकास विभाग और राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा मोनिका रानी ने सोशल ऑडिट निदेशालय के निदेशक को समझौते की हस्ताक्षरित प्रति भेज दी है। साथ ही अग्रिम भुगतान के रूप में निर्धारित 50 प्रतिशत धनराशि हस्तांतरित करने के लिए बैंक खाते का पूरा विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है, जिससे भुगतान की प्रक्रिया समय से पूरी हो सके।समझौते का मुख्य उद्देश्य समग्र शिक्षा योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करना है। इसके तहत योजना से जुड़े वित्तीय अभिलेखों, वाउचर, अनुदान वितरण और अन्य जरूरी दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इसके साथ ही योजनाओं के भौतिक लक्ष्यों और उपलब्धियों का भी आकलन होगा। लाभार्थियों का मौके पर सत्यापन और नमूना जांच कराई जाएगी। सोशल ऑडिट निदेशालय की टीम जांच के दौरान सामने आने वाली कमियों, वित्तीय अनियमितताओं और सुधार के सुझावों को शामिल करते हुए विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी।

समझौते में दोनों पक्षों की जिम्मेदारियां भी तय की गई हैं। समग्र शिक्षा की ओर से सोशल ऑडिट के लिए जरूरी फाइलें, अभिलेख, आंकड़े और अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा निरीक्षण और क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान ऑडिट टीम को आवश्यक सहयोग दिया जाएगा तथा निर्धारित शर्तों के अनुसार भुगतान किया जाएगा। वहीं सोशल ऑडिट निदेशालय तय समय सीमा में निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपेगा।

ऑडिट के दौरान प्राप्त आंकड़ों और विभागीय जानकारियों की गोपनीयता बनाए रखना भी उसकी जिम्मेदारी होगी। बिना अनुमति कोई भी दस्तावेज या रिपोर्ट किसी अन्य संस्था, व्यक्ति अथवा मीडिया के साथ साझा नहीं की जा सकेगी।समझौते के अनुसार हस्ताक्षर होने के 15 दिनों के भीतर सोशल ऑडिट की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और इसे छह माह में पूरा करना होगा। ऑडिट समाप्त होने के दो माह के भीतर अंतरिम और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है। समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर की तारीख से एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा।इस पूरी प्रक्रिया के लिए 20 करोड़ 93 लाख 30 हजार 947 रुपये का बजट निर्धारित किया गया है। इसका भुगतान तीन चरणों में किया जाएगा। समझौते पर हस्ताक्षर के बाद 50 प्रतिशत धनराशि अग्रिम दी जाएगी। चिह्नित विद्यालयों में से 50 प्रतिशत का सोशल ऑडिट पूरा होने पर 30 प्रतिशत और अंतिम रिपोर्ट सौंपने के बाद शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा।समझौते में शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में 15 दिन का लिखित नोटिस देकर इसे समाप्त करने का प्रावधान भी रखा गया है। किसी विवाद या मतभेद की स्थिति में दोनों विभागों के विभागाध्यक्ष अथवा सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों के लिए मान्य होगा। माना जा रहा है कि इस पहल से परिषदीय विद्यालयों में योजनाओं के संचालन की वास्तविक स्थिति सामने आएगी और प्राप्त सुझावों के आधार पर शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।

विकास कार्यों पर उठे सवाल, अपात्रों को आवास देने और मनरेगा में धन के दुरुपयोग के आरोप

पांच वर्षों के विकास कार्यों की जांच कराने की मांग, हैंडपंप रिबोर से लेकर तालाब खुदाई तक में अनियमितता का दावा

(जीएनएस)।

बीसलपुर/पीलीभीत। बिलसंडा विकासखंड की ग्राम पंचायत पिपरिया संजरपुर में ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव पर सरकारी धन के दुरुपयोग तथा विकास कार्यों में अनियमितता के गंभीर आरोप लगे हैं। गुरुवार को गांव में एकत्र हुए ग्रामीणों ने पंचायत में कराए गए विकास कार्यों पर सवाल उठाते हुए पिछले पांच वर्षों के कार्यों और सरकारी योजनाओं की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की।

ग्रामीणों का आरोप है कि हैंडपंप रिबोर के नाम पर लाखों रुपये की धनराशि निकाली गई, जबकि मौके पर केवल एक हैंडपंप का ही रिबोर कराया गया। पंचायत भवन के निर्माण में भी अनियमितता का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों के मुताबिक, भवन बने अभी चार वर्ष ही हुए हैं, लेकिन



उसकी हालत खराब होने लगी है। ग्राम सचिवालय में इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर, फर्नीचर और अन्य उपकरण ग्राम प्रधान द्वारा निजी इस्तेमाल के लिए अपने घर में रखे जाने का भी आरोप है। ग्रामीणों का कहना है कि सचिवालय अधिकतर समय बंद रहता है। गांव का सामुदायिक शौचालय भी बंद पड़ा रहता है।

आवास योजना को लेकर भी ग्रामीणों ने पक्षपात का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अपात्र लोगों को आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है, जबकि जरूरतमंद और पात्र परिवार योजना से वंचित हैं। वहीं, दियोरिया रोड से गुड्डू के घर तक कराए गए इंटरलॉकिंग कार्य में पुराने खड़ंजे की ईंटें उखाड़कर ग्राम प्रधान द्वारा अपने घर में लगवाने का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों का दावा है कि रास्ते का निर्माण सरकारी धन से कराने के बजाय ग्रामीणों से चंदा एकत्र कर कराया गया।

इसके अलावा चमरइया तालाब की पांच वर्षों में दो बार और दोहवा तालाब की तीन बार खुदाई दर्शाकर सरकारी धनराशि निकालने का आरोप लगाया गया है। तालाबों के सौंदर्यीकरण के नाम पर भी दो बार भुगतान कराने तथा चकरोडों पर एक ही कार्य को दो बार दर्शाकर धनराशि निकालने का दावा किया गया है।

मनरेगा कार्यों में भी अनियमितता के आरोप लगाए गए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक, जयदेव, छत्रपाल, अनिल, सुशील, आनंद पाल, लालजीत और सुधीर सहित कई लोगों के खातों में मनरेगा की धनराशि भेजी गई। आरोप है कि मनरेगा के नाम पर सरकारी धन का दुरुपयोग कर बंदरबांट की गई।

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि ग्राम पंचायत में पिछले पांच वर्षों के सभी विकास कार्यों, मनरेगा भुगतान, आवास आवंटन, हैंडपंप रिबोर और तालाबों की खुदाई से संबंधित अभिलेखों की निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही स्थलीय सत्यापन कराकर आरोपों की पुष्टि होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

मिसाल बनी हिंदू-मुस्लिम एकता, दोस्त को बचाने के लिए मुस्लिम पत्रकार ने सीने पर खाया चाकू का वार

आज एक बार फिर यह कहावत चरितार्थ हो गई-जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई

(जीएनएस)।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी के रहने वाले तारिक खान और संतोष शर्मा की दोस्ती ने इंसानियत, भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द की ऐसी मिसाल पेश की है, जिसे हर किसी को देखना और समझना चाहिए। एक ओर जहां संतोष शर्मा को बचाने के लिए उनके मुस्लिम दोस्त तारिक खान ने अपनी जान की परवाह किए बिना चाकू का वार अपने ऊपर झेल लिया, वहीं दूसरी ओर इस घटना ने साबित कर दिया कि दोस्ती और इंसानियत का कोई मजहब नहीं होता। दोनों ही ईमानदार पत्रकार हैं। एक हिंदू और दूसरा मुस्लिम, लेकिन उनके बीच का रिश्ता मजहबी पहचान से कहीं ऊपर है। जब दोस्त की जान पर बन आई तो तारिक खान ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर दोस्त को बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल दिया। यह घटना उन लोगों के लिए भी एक करारा जवाब है, जो समाज में नफरत की दीवारें खड़ी कर धर्म के नाम पर डर और विभाजन की राजनीति करते हैं। अक्सर सवाल उठाया जाता है कि हिंदू खतरे में है या मुस्लिम खतरे में है, लेकिन ऐसी घटनाएं बताती हैं कि असली खतरा मजहब से नहीं, बल्कि नफरत और इंसानियत के दुश्मनों से है। तारिक खान और संतोष शर्मा की दोस्ती ने एक बार फिर बता दिया कि खून का रिश्ता जरूरी नहीं, दिल का रिश्ता भी जान देने और बचाने का हौसला रखता है। इंसानियत जिंदा है, मोहब्बत जिंदा है और हिंदू-मुस्लिम भाईचारा आज भी कायम है।



प्रदेश के 20 प्रदूषण जांच केन्द्रों के प्राधिकार-पत्र निलम्बित, जांच पर लगी रोक

(जीएनएस)।

लखनऊ, वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण और प्रदूषण जांच व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग ने प्रदेश के 20 प्रदूषण जांच केन्द्रों के खिलाफ कार्रवाई की है। इन सभी केन्द्रों के प्राधिकार-पत्र अग्रिम आदेशों तक निलम्बित कर दिए गए हैं। निलम्बन की अवधि में ये केन्द्र किसी भी वाहन की प्रदूषण जांच नहीं कर सकेंगे और न ही प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र जारी कर पाएंगे।परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन ने बताया कि विभाग की ओर से विभिन्न जनपदों में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों (प्रशासन) के माध्यम से मान्यता प्राप्त प्रदूषण जांच केन्द्रों का निरीक्षण कराया गया था। इस दौरान कई केन्द्रों की कार्यप्रणाली में निर्धारित मानकों और तकनीकी प्रक्रियाओं के उल्लंघन की शिकायतें सामने आईं। विभाग ने इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित केन्द्र संचालकों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया और कारण बताओ नोटिस जारी कर लिखित स्पष्टीकरण मांगा।उन्होंने बताया कि निर्धारित समयावधि में संतोषजनक जवाब नहीं देने वाले 20 केन्द्रों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश ऑनलाइन मोटरयान प्रदूषण जांच केन्द्र योजना-2020 के प्रस्तर-7(प) के तहत कार्रवाई की गई है। इनके प्राधिकार-पत्र अग्रिम आदेशों तक निलम्बित कर दिए गए हैं। इस अवधि में यदि कोई केन्द्र जांच करता है या प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र जारी करता पाया गया तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।परिवहन आयुक्त ने सभी संभागीय और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्रों में संचालित सभी मान्यता प्राप्त प्रदूषण जांच केन्द्रों से निर्धारित मानकों, तकनीकी प्रावधानों और प्रक्रिया का पूरी तरह पालन सुनिश्चित कराएं। बिना वास्तविक जांच के प्रमाण-पत्र जारी करना अथवा जांच प्रक्रिया में किसी भी तरह की अनियमितता बरतना गंभीर उल्लंघन माना जाएगा।उन्होंने कहा कि वाहनों की वास्तविक प्रदूषण स्थिति का सही आकलन करने और प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने के लिए जांच केन्द्रों का निरीक्षण और निगरानी अभियान आगे भी जारी रहेगा।

विकास कार्यों की खुली पोल, बदहाल सड़कें और खराब नल बने ग्रामीणों की परेशानी

ग्राम पंचायत में सड़कों के नाम पर विकास कार्य न होने का आरोप, नलों की बदहाल स्थिति और बंद पड़े ग्रामीण सचिवालय से ग्रामीण परेशान

(जीएनएस)।

बीसलपुर/पीलीभीत। बीसलपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत खाकुमा में बुनियादी सुविधाओं की बदहाली को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। गांव में सड़कों की हालत बेहद खराब है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़कों के नाम पर कोई ठोस विकास कार्य नहीं कराया गया, जिसके चलते जगह-जगह सड़कें टूटी और जर्जर पड़ी हैं। बरसात के दिनों में ग्रामीणों को आवागमन में और भी अधिक परेशानी उठानी पड़ती है।

वहीं, गांव में पेयजल व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है। ग्रामीणों का कहना है कि नलों की स्थिति ठीक नहीं है और कई जगह पानी की समस्या बनी हुई है। जिम्मेदारों की



अनदेखी के चलते ग्रामीणों को पेयजल जैसी बुनियादी सुविधा के लिए भी परेशान होना पड़ रहा है।

इसके अलावा गांव का ग्रामीण सचिवालय भी अक्सर बंद रहने का आरोप है। सचिवालय पर ताला लटका रहने से ग्रामीणों को पंचायत स्तर के जरूरी कामों के लिए इधर-उधर भटकना पड़ता है। छोटे-छोटे कार्यों के लिए ग्रामीणों को तहसील के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि गांव में विकास कार्यों के नाम पर दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर सड़क, पेयजल और पंचायत सचिवालय जैसी मूलभूत सुविधाओं की स्थिति बदहाल है। ग्रामीणों ने संबंधित अधिकारियों से गांव की सड़कों, नलों और बंद पड़े सचिवालय की व्यवस्था की जांच कराकर समस्याओं का समाधान कराने की मांग की है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी ग्रामीणों की इन समस्याओं पर कब ध्यान देते हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना ने बदली हंसा राजभर की जिंदगी, पक्के घर में शुरू किया सिलाई का काम

(जीएनएस)।

लखनऊ, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) ने आजमगढ़ की हंसा राजभर के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। कभी कच्चे और जर्जर मकान में परिवार के साथ मुश्किलों का सामना करने वाली हंसा आज पक्के घर में रह रही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इसी घर में सिलाई का काम शुरू कर अपनी आमदनी का जरिया भी तैयार कर लिया है। अब वह परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी निभाने के साथ बच्चों की पढ़ाई में भी योगदान दे रही हैं।आजमगढ़ के नगर पालिका परिषद मुबारकपुर के वार्ड नंबर छह, अमिलो खास निवासी हंसा राजभर पत्नी धर्मेन्द्र कुमार का परिवार पहले कटरैन और टट्टर से बने एक जर्जर मकान में रहता था। परिवार के सभी सदस्यों के लिए एक ही कमरा था। बरसात में छत से पानी टपकता था और गर्मी में तेज धूप सीधे कमरे के भीतर आती थी। ऐसे हालात में बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती थी। किताबें भीग जाती थीं और पढ़ने के लिए न पर्याप्त जगह थी और न ही रोशनी की व्यवस्था।हंसा के मुताबिक, उनके पति की छोटी सी सब्जी की दुकान है। दिनभर मेहनत करने के बावजूद इतनी आमदनी नहीं हो पाती थी कि परिवार पक्का मकान बनवा सके। घर का खर्च चलाना ही मुश्किल था, ऐसे में पक्का मकान बनाना उनके लिए एक सपना बनकर रह गया था। इसी दौरान मोहल्ले की आशा बहू के माध्यम से उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की जानकारी मिली। योजना के तहत गरीब परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए सरकारी सहायता दिए जाने की जानकारी मिलने पर उन्होंने डूडा कार्यालय पहुंचकर आवेदन किया।डूडा कार्यालय में अधिकारियों ने उन्हें योजना की पात्रता और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी। जरूरी दस्तावेज और औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उनका आवेदन स्वीकृत हो गया और आवास निर्माण के लिए उनके बैंक खाते में सहायता राशि पहुंचने लगी।



इसके बाद उन्होंने पक्के मकान का निर्माण कराया। आज उनके घर में दो कमरे, एक रसोई और पक्का शौचालय है। हंसा का कहना है कि अब उनके बच्चे सुरक्षित माहौल में पढ़ाई कर रहे हैं। बारिश के दौरान घर में पानी आने का डर नहीं रहता। पक्के मकान और शौचालय से परिवार, खासकर महिलाओं और बेटी की सुरक्षा और सुविधा बढ़ी है।हंसा के जीवन में बदलाव केवल आवास मिलने तक सीमित नहीं रहा। पक्का घर बनने के बाद उन्होंने इसी में सिलाई का काम शुरू करने का फैसला किया। इसके लिए सिलाई मशीन खरीदी और मोहल्ले के लोगों के कपड़े सिलने लगीं। धीरे-धीरे उनके काम से परिवार की आमदनी बढ़ने लगी। पहले वह पूरी तरह पति की कमाई पर निर्भर थीं, लेकिन अब अपनी आय से परिवार के खर्च में हाथ बंटा रही हैं। वह बच्चों की स्कूल फीस भी खुद जमा करती हैं। उनके मुताबिक, बच्चों की पढ़ाई में आर्थिक योगदान दे पाना उनके लिए गर्व की बात है।हंसा राजभर ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ उन्हें स्वनिधि योजना का भी लाभ मिला, जिससे उन्होंने सिलाई के काम को आगे बढ़ाया।

उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार जताया। उनका कहना है कि सरकारी योजनाओं से मिले सहयोग ने उनके परिवार के रहन-सहन और आर्थिक स्थिति में बदलाव लाने में मदद की है।

धान खरीद की सुस्त रफ्तार पर किसान संगठन ने उठाए सवाल, राइस मिलरों पर लगाए आरोप

14 नवंबर तक किसी भी क्रय केंद्र पर एक हजार क्विंटल धान की तौल नहीं होने का दावा, खरीद व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग

(जीएनएस)।

बीसलपुर (पीलीभीत)। बीसलपुर नवीन मंडी में धान खरीद की धीमी रफ्तार को लेकर राष्ट्रीय किसान क्रांति यूनियन ने सवाल खड़े किए हैं। यूनियन के युवा मंडल अध्यक्ष (बरेली) संचित दीक्षित ने मंडी में संचालित धान क्रय केंद्रों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए आरोप लगाया कि 14 नवंबर तक किसी भी क्रय केंद्र पर एक हजार क्विंटल धान की तौल नहीं हो सकी है। उनका दावा है कि एजेंसी के क्रय केंद्र हों या भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के, किसी पर भी खरीद



का आंकड़ा संतोषजनक नहीं है।

संचित दीक्षित ने कहा कि क्रय केंद्रों पर प्रतिदिन 300 से 600 क्विंटल तक धान तौलने की क्षमता है, इसके बावजूद क्षमता के अनुरूप खरीद नहीं की जा रही है। उन्होंने आशंका जताई कि आने वाले दिनों में राइस मिलर किसानों से कम कीमत पर खरीदे गए धान को किसानों के अंगूठे लगवाकर सरकारी खरीद में दर्ज करा सकते हैं। हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

उन्होंने आरोप लगाया कि राइस मिलरों की कथित मनमानी से सरकारी धान खरीद व्यवस्था प्रभावित हो रही है। शासन-प्रशासन से मांग की कि पूरे मामले की निगरानी कराई जाए और सरकारी खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने कहा कि मंडी किसानों के लिए है और किसान अपनी उपज लेकर कभी भी यहां आ सकते हैं। किसी को भी किसानों के मंडी आने से रोकने का अधिकार नहीं है। संचित दीक्षित ने यह भी आरोप लगाया कि राइस मिलरों की ओर से किसान संगठन के पदाधिकारियों के मंडी पहुंचने पर आपत्ति जताई गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसान संगठन किसानों की समस्याएं उठाने के लिए मंडी पहुंचता रहेगा। साथ ही प्रशासन से किसानों के हितों की रक्षा करने और धान खरीद व्यवस्था को नियमानुसार संचालित कराने की मांग की।